DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

29 October 2022

वन नेशन, वन पुलिस यूनिफॉर्म

❖ संदर्भ

➢ हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय पुलिस बलों के लिए "एक राष्ट्र, एक वर्दी" का विचार रखा गया है।

❖ मुख्य बिंदु

- प्रधानमंत्री का सुझाव "एक राष्ट्र, एक वर्दी" देश भर में नीतियों का एक समान सेट पेश करने के उनके व्यापक प्रयास के अनुरूप है।
- सरकार पहले ही 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रारम्भ कर चुकी है; 'एक राष्ट्र, एक गतिशीलता कार्ड'; 'एक राष्ट्र, एक सांकेतिक भाषा', एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना भी।

❖ विधि और व्यवस्था राज्य का विषय है

- भारतीय संविधान पुलिस बलों को राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखता है।
- 28 राज्यों में से प्रत्येक का अपना पुलिस बल है।
- 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' दोनों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) में रखा गया है।

❖ पुलिस यूनिफार्म

- भारत में पुलिस कर्मियों को अक्सर खाकी रंग के साथ देखा जाता है।
- अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी वर्दी अलग-अलग डिग्री में भिन्न होती है।
- चूंकि राज्य सरकारें और यहां तक कि एक व्यक्तिगत बल भी यह तय कर सकता है कि उनके कर्मचारी किस तरह की वर्दी पहन सकते हैं, कई बार उनकी आधिकारिक पोशाक में विसंगतियां होती हैं। उदाहरण के लिए:
  - कोलकाता पुलिस सफेद वर्दी पहनती है।
  - पुडुचेरी पुलिस के सिपाही अपनी खाकी वर्दी के साथ चमकदार लाल टोपी पहनते हैं।
  - दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान सफेद और नीले रंग की वर्दी पहनते हैं।

अतिरिक्त मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक

❖ संदर्भ

➢ हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह 3 नवंबर, 2022 को एक अतिरिक्त एमपीसी बैठक आयोजित करेगा।

❖ मुख्य बिंदु

• इस बैठक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के रूप में बुलाया गया है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लक्ष्य को 2-6 प्रतिशत के दायरे में बनाए रखने में विफल रहा है।
• सीपीआई लगातार तीन तिमाहियों, या जनवरी से सितंबर 2022 तक इस सीमा से बाहर रहा है।
• यह बैठक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडएन के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित की जा रही है।
• पहली बार अधिनियम की धारा 45जेडएन के प्रावधानों के अंतर्गत एमपीसी की बैठक बुलाई गई है।
• केंद्रीय बैंक ने आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के विनियम 7 और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियमन, 2016 का भी हवाला दिया है।
RBI अधिनियम की धारा 45 जेडएन(45ZN)
• इसमें कहा गया है कि यदि आरबीआई मुद्रास्फीति के लक्ष्य को पूर्ण में विफल रहता है, तो उसे विफलता के कारणों की व्याख्या करते हुए सरकार को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी।
• रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक का उल्लेख करना होगा –
- इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।
- एक अनुमानित समय जिसके भीतर प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाइयों के समय पर

❖ मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के विषय में :

- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी (45ZB) के अंतर्गत, केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
- इस तरह के पहले एमपीसी का गठन 29 सितंबर 2016 किया गया था।

- **कार्य:**
  - यह नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है
  - महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक मत समान होने की स्थिति में राज्यपाल के पास निर्णायक मत होने पर बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।
  - मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंक पर बाध्यकारी होगा।
- **संरचना :** छह सदस्य (अध्यक्ष सहित) :
  - आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में होंगे।
  - मौद्रिक नीति के प्रभारी उप राज्यपाल होंगे।
  - केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

कार्यान्वयन के पश्चात मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
• आरबीआई एमपीसी और मौद्रिक नीति प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 7 में कहा गया है कि - सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा और प्रारूप तैयार करने के लिए सामान्य नीति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में एक अलग बैठक निर्धारित करने की आवश्यकता है।

अधिकारी होगा।
• तीन व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

एनडीसी संश्लेषण रिपोर्ट

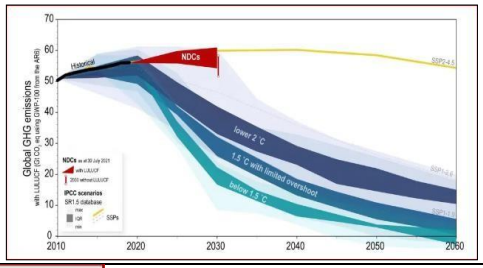

❖ संदर्भ

➢ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए देशों द्वारा दिए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) अपर्याप्त हैं।

❖ मुख्य बिंदु

• नवीनतम एनडीसी के आधार पर 2020-2030 में संचयी कार्बन डाई ऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन, शेष कार्बन बजट का 86% उपयोग करने की संभावना है।
• एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट इंगित करती है कि समय के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम किया जा रहा है।
रिपोर्ट के विषय में
• यूएनएफसीसीसी की संश्लेषण रिपोर्ट देशों द्वारा की गई जलवायु प्रतिबद्धताओं और वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का एक वार्षिक सारांश है।

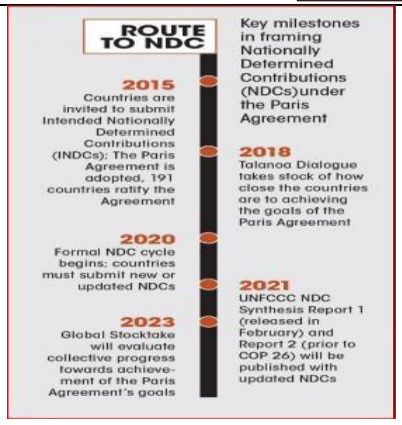

• राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के रूप में जानी जाने वाली इन प्रतिबद्धताओं को उन देशों द्वारा किया गया था जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

वैश्विक टीबी रिपोर्ट

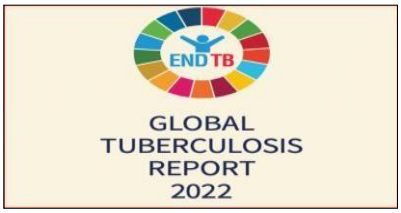

❖ संदर्भ

➢ हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक टीबी रिपोर्ट जारी किया गया हैं।

❖ मुख्य बिंदु

• अनुमानित 10.6 मिलियन लोग 2021 में तपेदिक (टीबी) से बीमार पाए गए और 2020 से 4.5% की वृद्धि हुई, तथा 1.6 मिलियन लोगों की मृत्यु टीबी से हुई (एचआईवी पॉजिटिव लोगों में 1,87,000 लोगों सहित)।
• कई वर्षों में यह पहली बार है कि टीबी और दवा प्रतिरोधी टीबी से बीमार लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।
• **कोविड का प्रभाव**: 2021 में कोविड-19 महामारी से तपेदिक से सम्बंधित सेवाएं बाधित हुई हैं, लेकिन टीबी की प्रतिक्रिया पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर रहा है।
लघु लाभ
• **सात देशों** - भारत, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, संयुक्त

❖ टीबी के विषय में:

• क्षय रोग (टीबी) रोगाणुओं के कारण होने वाली एक बीमारी है जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है।
• यह माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है।
• टीबी सामान्यतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य हिस्सों, जैसे मस्तिष्क, गुर्दे या रीढ़ को भी प्रभावित कर सकता है।

गणराज्य तंजानिया, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे - ने **सामूहिक रूप से उन लोगों में से 82% का अनुमान** लगाया जिन्होंने 2021 में निवारक उपचार प्रारम्भ किया था।

• इस क्षेत्र में सात उच्च टीबी बोझ वाले देश-इथियोपिया, केन्या, लेसोथो, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त गणराज्य तंजानिया और जाम्बिया- ने **2015 की तुलना में 2020 में टीबी की घटनाओं की दर में 20% की कमी** के मील के पत्थर को पार कर लिया है। .

• **टीबी से ग्रसित लोगों का अनुपात, 2020 में 33% से बढ़कर 2021 में 38% हो गया**, जिनका प्रारम्भ में तेजी से निदान के साथ परीक्षण किया गया था।

जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियां (DISHA)

❖ संदर्भ

➢ केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किश्तवाड़ जिले में होने वाली विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए दिशा बैठक की अध्यक्षता की है।

❖ दिशा के विषय में

• कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों केमध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों (दिशा) का गठन किया गया है।

• यह एक सरकार की व्यापक पहल है जो सहभागी शासन और विचारशील लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहती है।

दिशा जिला स्तर पर सभी विकास गतिविधियों की त्रैमासिक समीक्षा की सुविधा प्रदान करके इसे प्राप्त करना चाहती है।

• दिशा समिति का अध्यक्ष जिले से निर्वाचित और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य (लोकसभा) होता है।

• दिशा समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर सांसद की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है, और इसमें जिले के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी भाग लेते हैं।

• दिशा समितियों के पास दिशा बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की मांग करने की शक्ति है।

• जिला कलेक्टर सदस्य सचिव होता है जो बैठक आयोजित करने और प्रभावी तथा समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होता है।

C-295MW परिवहन विमान निर्माण परियोजना

❖ संदर्भ

➢ प्रधानमंत्री द्वारा 30 अक्टूबर 2022 को वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C-295MW परिवहन विमान निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी।

❖ मुख्य बिंदु

• यह परिवहन विमान निर्माण परियोजना देश में विमानन क्षेत्र के लिए पूर्ण रूप से एक नई पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी।

• यह सुविधा परिवहन विमान निर्माण में भारत की समग्र स्थिति को बढ़ाएगी।

• यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा।

विमान भारतीय वायुसेना की रसद क्षमताओं को मजबूत करेगा।

• 16 विमान उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे और 40 का निर्माण भारत में भारतीय विमान ठेकेदार, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के टाटा कंसोर्टियम और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा किया जाएगा।

• विमान का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। सभी 56 परिवहन विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया जाएगा।

• परिवहन सुविधा से कई कुशल और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

29 October 2022

संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ

सीएआर-टी सेल उपचार

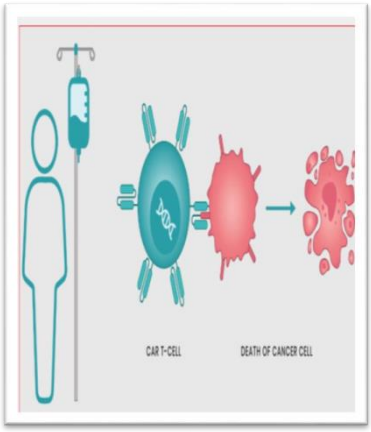

❖ **संदर्भ**

➢ हाल ही में आईआईटी-बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के बीच एक संयुक्त प्रयास से आठ वर्षीय बच्ची को भारत की पहली स्वदेशी निर्मित सीएआर-टी कोशिकाओं के लिए सुरक्षा परीक्षण के हिस्से के रूप में उपचार किया गया।

सीएआर टी-सेल थेरेपी क्या है?

• काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (सीएआर) टी-सेल थेरेपी, टी कोशिकाओं (एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका) नामक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रयोगशाला में परिवर्तित कर कैंसर से लड़ने के लिए प्राप्त करने की एक विधी है, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं को खोजकर नष्ट कर सकें।

• सीएआर टी-सेल थेरेपी को कभी-कभी एक प्रकार की सेल-आधारित जीन थेरेपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टी कोशिकाओं के भीतर जीन को परिवर्तित करना शामिल है ताकि उन्हें कैंसर के उपचार में सहायता मिल सके।

• इस प्रकार का उपचार जब अन्य उपचार काम नहीं कर रहे हों तो यह कैंसर के उपचार में बहुत सहायक हो सकता है।

• इसमें कुछ आनुवंशिक सामग्री के साथ शरीर की टी प्रतिरक्षा कोशिकाओं की फिर से इंजीनियरिंग करना शामिल है ताकि वे विनाश के लिए चुनिंदा रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर सकें।

फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर

❖ **संदर्भ**

➢ हाल ही में, एक फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर (FTB) ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय द्वारा आयोजित भारत के जल निकायों की सफाई और पुनर्स्थापना चुनौती को जीता है।

❖ **मुख्य बिंदु**

• फ्लोटिंग ट्रैश बैरियर एक बेंगलुरु फर्म (AlphaMERS Ltd) द्वारा विकसित किया गया था तथा जल निकायों में कचरा रोकने के लिए पूरे भारत के आठ शहरों में तैनात किया गया है।

• FTB के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक जूरी पैनल द्वारा किया गया जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञ शामिल थे।

• पैनल ने पाया कि तैरता कचरा अवरोध भारत के जलाशयों में तैरते ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे को संबोधित कर सकता है।

• एफटीबी पानी के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग कचरे को नदी तट पर लाने के लिए करता है जहां इसे तैनात किया जाता है और वहां से कचरा मैन्युअल या यांत्रिक रूप से हटा दिया जाता है।

• एफटीबी आठ शहरों - बेंगलुरु, चेन्नई, पुडुचेरी, हैदराबाद, मैसूर, तंजावुर, तूतीकोरिन और कोयंबटूर में तैनात है।

हट्टी समुदाय

❖ **संदर्भ**

➢ केंद्र द्वारा हाल ही में सिरमौर जिले में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में लाने की घोषणा से कुछ वर्गों द्वारा नाराजगी जताई रही है।

❖ **हटी समुदाय के विषय में**

• सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी क्षेत्र में हट्टी समुदाय काफी हद तक केंद्रित है।

• समुदाय के सदस्य समय के साथ शिमला और सोलन जिले में और उसके आसपास के क्षेत्रो में बस गए हैं।

• समुदाय, जिसमें तीन लाख से अधिक लोग हैं, का नाम उनके आस-पास के शहरों में 'हाट' नामक छोटे बाजारों में अपने घर

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

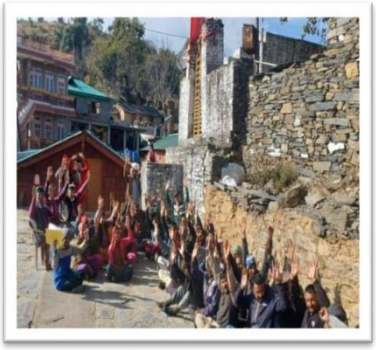

में उगाई जाने वाली फसलों को बेचने की पुरानी पेशेवर प्रथा के नाम पर रखा गया है।

• आज तक, इस समुदाय के सदस्यों को मुख्यधारा में नहीं लाया गया है और अधिकांश पशु पालन और कृषि पर निर्भर हैं।

• पंचायत प्रणाली की स्थापना के बावजूद वे अभी भी खुंबली - पारंपरिक परिषद का पालन करते हैं।

• यह बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-गिरी क्षेत्र का हट्टी समुदाय उत्तराखंड के जौनसार-बावर क्षेत्र के जौनसार समुदाय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक समानताएं साझा करता है।

- ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांस-गिरी क्षेत्र और जौनसार बावर क्षेत्र, तत्कालीन सिरमौर रियासत का हिस्सा थे।
- संयोग से, जो लोग जौनसार बावर क्षेत्र को पार कर गए, जो अब उत्तराखंड में है, 1967 से आदिवासी स्थिति का आनंद लेते हैं।

कन्नड़ विधेयक में तुलु और कोडवा भाषाएँ

❖ **संदर्भ**

➢ कर्नाटक में तुलु और कोडवा बोलने वालों के वर्गों ने कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक, 2022 के प्रारूप में भी अपनी भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग की है।

❖ **मुख्य बिंदु**

• इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में कन्नड़ के "व्यापक उपयोग और प्रचार" को सुनिश्चित करना है।

• विधेयक उच्च शिक्षा में कन्नड़ लोगों को आरक्षण प्रदान करने, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों के साथ उद्योगों को प्रोत्साहन जोड़ने और कन्नड़ भाषा को प्रधानता देने का प्रयास करता है।

• कई तुलु और कोडवा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए खतरा है।

❖ **तुलु और कोडवा भाषा के विषय में :-** दोनों भाषाएं द्रविड़ भाषाएं हैं।

• **तुलु** :

- वितरण- तुलु भाषी कर्नाटक के दो तटीय जिलों और केरल के कासरगोड जिले में केंद्रित हैं।
- जनसंख्या- 2001 की जनगणना के अनुसार 17,22,768 वक्ता।
- तुलु में लोक-गीत रूपों जैसे पद्दना, और पारंपरिक लोक रंगमंच यक्षगान के साथ एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा है।

• **कोडवा :**

- यह कोडगु जिले में बोली जाती है।
- इसे कुर्गी के नाम से भी जाना जाता है।
- जनसंख्या - 2001 की जनगणना के अनुसार 166,187 वक्ता।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare